

पत्र संख्या : फा0स0 २०/2011

कार्यालय
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद

दिनांक : फरवरी, 17, 2011

सेवा में,
नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: मै0 क्रासिंग रिपब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

सन्दर्भ: पत्रांक 682/मा0प्ला0/10 दिनांक 10.12.2010

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मै0 क्रासिंग रिपब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 ईडब्ल्यूएस प्लाट नं0-2ए, क्रासिंग रिपब्लिक खसरा संख्या 143,146,148,149,286 एवं 287 ग्राम डूंडाहेड़ा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन जिसका कुल प्लाट ऐरिया 14378.00 वर्ग मीटर प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया ग्राउन्ड फ्लोर 4194.30 वर्ग मीटर, प्रस्तावित टोटल एफ0ए0आर0 16778.84 वर्ग मीटर एवं भवन की ऊँचाई 11.81 मीटर प्रस्तावित है, संलग्न भवन मानचित्र एवं साइट प्लान का अवलोकन उपरान्त स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद द्वारा कराया गया, सन्तोषजनक है।

भवन में सेट बैक / स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में निर्णय आप द्वारा अपेक्षित है। भवन निर्माण कार्यों में उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 का अनुपालन भी भवन निर्माता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

भवन में अग्नि से सुरक्षा का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के अनुरूप कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु मानचित्र/साइट प्लान का प्राथमिक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : मै0 मै0 क्रासिंग रिपब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 542/mp/211

दिनांक : 22/11/2011

मानचित्र संख्या : 952/ईएचए/2009-10

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि.(कन्सॉर्शियम)

द्वारा निदेशक श्री अशोक चौधरी,

एच-174, सैक्टर-63, नौएडा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.09 के संदर्भ में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्ड संख्या 2-ए इंडाहेडा, गाजियाबाद पर विकासकर्ता कम्पनी के स्वामित्वाधीन भूमि पर प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्रों की इस स्वीकृत से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जौ0डी0ए0 अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 4- यदि भविष्य में कोई भी व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 5- एच.टी.लाइन एवं अन्य बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अंदर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 6- सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 7- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन में स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
- 8- वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- 9- रैम्प का निर्माण अपनी ही भूमि पर सड़क अथवा लेन को बिना प्रभावित किये करना होगा।
- 10- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम / शर्तों का पालन करना होगा।
- 11- प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.09.09 का अनुपालन विकासकर्ता को करना होगा।
- 12- ग्राम समाज अथवा नगर निगम की भूमि को यथावत रखा जायेगा। यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करायी जाती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग की शर्तों का पालन करना होगा।

13. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.2005 के अनुसार एवं शासनादेश दिनांक 28.11.06 के क्रम में समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै. क्रासिंग इन्फ्रा. प्रा.लि. (कन्सॉर्शियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे परन्तु प्रस्तावित टाउनशिप में कतिगय ट्रंक सुविधायें जैसे रोड कनेक्शन, ड्रेनेज एवं सीवेज निस्तारण, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट आदि सुविधायें विकासकर्ता कंपनी को वास्तविक व्यय के ऊपर 15% सुपरविजन चार्ज जोड़कर उपलब्ध करायी जा सकती है। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका सीधा लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
14. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
15. अग्निशमन विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.11 व अनुमोदित मानचित्र की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
17. संदर्भित ई.डब्लू.एस. भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
18. एल.एम.सी./ नगर निगम की भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा रही है। प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
19. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि को विकासकर्ता कंपनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा तदोपरान्त ही प्लैट का कब्जा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दिया जायेगा।

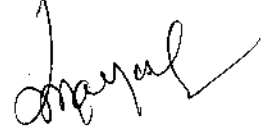
20. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईंग तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। डी.पी.आर. के स्वीकृत तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001(आ.ब.) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रीट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता /आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन

से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

- 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
 - 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्।
 - 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल् इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
 - 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 - 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
- 21- प्राधिकरण द्वारा यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त शुल्क रोपित किया जाता है तो उसे प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
 - 22- विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
 23. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।
 24. प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवन निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश संख्या 5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.2010 के अनुसार रखनी होंगी।
 25. ई.डब्ल्यू.एस. भवनों की लागत का अनुमोदन शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर कराकर नियमानुसार भवनों का आवंटन पात्र व्यक्तियों को कराना होगा।
 26. मानचित्र में कन्वीनियन्ट शॉप हेतु दर्शित क्षेत्रफल पर उपयोग से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण करना होगा।
 27. प्रस्तावित योजना का अनुरक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक इसे नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता है एवं नगर निगम को हस्तान्तरित करने की जिम्मेदारी भी पक्ष की होगी। योजना का समुचित रूप से एवं सतत आधार पर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता तथा प्राधिकरण के मध्य ज्वाइंट वेंचर हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। आवंटियों से वसूल की जाने वाली एकमुश्त अनुरक्षण की धनराशि तथा वार्षिक यूजर चार्जेज 'एस्को एकाउन्ट' में जमा किए जायेंगे। टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे तथा ज्वाइन्ट वेंचर द्वारा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु एकत्रित धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए।

- 28- अग्निशमन के वाहनों के प्रयोग हेतु स्थल पर उपयुक्त स्थानों पर फायर हाइड्रेन्ट्स का प्राविधान पक्ष को करना होगा।
- 29- प्रस्तावित भवन हेतु आवश्यक कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 30- विद्युत व्यवस्था हेतु उ.प्र. पावर कारपोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
- 31- पूर्व में निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
- 32- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक : एक सैट स्वीकृत मानचित्र।



मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा0वि0प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक/संख्या 101724/सी-1/सहमति वायु/जी-1771/2017

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० (कासिंग रिपब्लिक),
एन० एच०-24, डुडाहेडा (इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप),
गाजियाबाद।

विषय: विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 98733/वायु सहमति/जी-1771/2017 दिनांक 24/03/17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा उद्योग को दिनांक 31/12/2017 तक शर्त सहमति वायु प्रदान की गयी है। आपने पूर्व में वायु सहमति आवेदन पत्र 2019 तक किया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 28/3/2017 द्वारा सहमति बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पूर्व में निर्गत वायु सहमति पत्रांक एफ 98733/वायु सहमति/जी-1771/2017 दिनांक 24/03/17 के साथ संलग्न सहमति वायु आदेश सं० 1771/सी-1/वायु सहमति आदेश/564/2017 दिनांक 22/3/2017 की वैधता अवधि दिनांक 31/12/2018 तक बढ़ाई जाती है। उक्त सहमति आदेश में निहित सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

अग्रवाल/-

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522 2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 2720676
ई-मेल: info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828
Fax: 0522 - 2720764 -
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक/संख्या- 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 (कासिंग रिपब्लिक),
एन0 एच0-24, डुडाहेडा (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप),
गाजियाबाद।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017/121 दिनांक 24/3/17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा उद्योग को दिनांक 31/12/2017 तक सशर्त सहमति जल प्रदान की गयी है। आपने पूर्व में जल सहमति आवेदन पत्र 2019 तक किया गया था। उद्योग को वर्ष 2017 तक जल सहमति प्रदान की गयी थी। उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 28/07/2017 के माध्यम से उद्योग को वर्ष 2018 तक सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पूर्व में निर्गत सहमति जल पत्रांक एफ 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017/121 दिनांक 24/3/17 के साथ संलग्न सहमति जल आदेश सं0 1983/सी-1/जल सहमति आदेश/606/2017 दिनांक 22/03/2017 की वैधता अवधि दिनांक 31/12/2018 तक बढ़ाई जाती है। उक्त सहमति आदेश में निहित सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

अग्रवाल/-

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522 2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828
Fax: 0522 - 2720764 -
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : docuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Shri Ashok Kumar,
COO,
M/s Crossings Infrastructure Pvt. Ltd,
Glass Gate, Near ABES Engg. College,
NH-24, Dhundera, Ghaziabad, U.P.-201009

Ref. No. 2099...../Parya/SEAC/1608/2013/TA(J)Date: 12 October, 2013

Sub: Environmental Clearance for Expansion of Residential Township Project "Crossing Republik"
Village-Dundahera, NH-24, Bypass Ghaziabad, U.P. M/s Crossings Infrastructure Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 14/05/2013, 01/07/2013, 06/09/2013, 21/09/2013 and 04/10/2013 addressed to the Secretary, SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meetings held on dated 18/06/2013 and 04/10/2013.

A Presentation was made by the representatives of project proponents along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd. The project proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:

1. The Environmental Clearance is sought for proposed Expansion of Residential Township Crossing Republicat Village-Dundahera, NH-24, Ghaziabad, U.P.
2. Project proponent through their letter dated 06/09/2013 have provided Khasra details of the proposed project as 121-123, 125-130, 143-149, 286-288, 293-349, 434, 435, 437, 438, 538-559, 571-580, 582-586, 588-593, 595, 596, 598-607, 620-657, 661-670, 677-695, 697, 704-707, 1198, 1200-1205.
3. Area details of the project are as follows:

| Particulars | Area (Sqm) | Area (Acres) |
|------------------------|------------------|--------------------|
| Total Township Area | 14,56,873 | 360.0 acres |
| Master Plan Green | 1,88,862 | 46.7 acres |
| Total Plot Area | 12,68,011 | 313.3 acres |

| Particulars | Area (Sqm) | Percentage |
|--------------------|------------|------------|
| Group housing | 7,12,389.8 | 56.2% |
| EWS/LIG | 66,420 | 5.2% |
| Commercial | 1,93,732.7 | 15.3% |
| Education facility | 79,005.13 | 6.2% |
| Medical facility | 40,893.24 | 3.2% |
| Community center | 7500 | 0.6% |
| Police Stn | 21,600 | 1.7% |
| Fire Stn. | 10,000 | 0.8% |
| LPG/ petrol Stn. | 3000 | 0.2% |
| Telephone Ex./P.O. | 5200 | 0.4% |
| Road Area | 1,28,270.1 | 10.1% |

4. Comparative Area statement from original proposals and expansion proposals are as follows:

| | ORIGINAL PROPOSAL(sqm) | | NEW EXPANDED PROPOSAL(sqm) | |
|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Total Plot Area | 14,56,873.2 | | | |
| FAR | | | | |
| Group Housing (18 Blocks) | 10,68,784.95 | FAR – 1.5 | 28,49,559.3 | FAR – 4.0 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Commercial | 2,06,631.84 | FAR - 1.2 | 7,74,930.8 | FAR - 4.0 |
| Institutional | 1,17,068.63 | FAR - 1.0 | 1,42,209.2 | FAR - 1.8 |
| EWS/LIG | 48,373.5 | FAR - 1.5 | 1,32,840.0 | FAR - 2.0 |
| Medical | 39,789.6 | FAR - 1.2 | 1,14,501.0 | FAR - 2.8 |
| Community | 13,500.0 | FAR - 1.5 | 11,250.0 | FAR - 1.5 |
| Others (Fire, Police etc.) | 26,824.9 | | 13,860.0 | |
| Total FAR | 15,20,973.5 | | 40,39,150.4 | |
| Basement Area | 13,54,716.0 | | 16,34,314.7 | |
| Facilities (Non -FAR) | 38,024.4 | | 1,00,978.7 | |
| Built Up Area | 29,13,714 | | 57,74,443.9 | |

5. Comparative Statement of Old and New facilities are as follows

| PARTICULARS | ORIGINAL PROPOSAL | NEW EXPANDED PROPOSAL |
|-----------------------------|--|---|
| Fresh Water | 7.8 MLD | 14.6 MLD |
| Recycled Water | 6.6 MLD | 6 MLD |
| Total Water Requirement | 14.5 MLD | 20.4 MLD |
| STP Capacity | CSTP of GDA | CSTP of GDA |
| Wastewater Generation | 9.4 MLD | 16 MLD |
| Source of Water Supply | Ground Water (till municipal supply is made available) | Ground Water & Ganga Jal (Applied) |
| Power Requirement | 63 MW | 85 MW |
| Backup Power (DG Sets) | 7 numbers of D.G sets each of 1 MW capacity | 7 numbers of D.G sets each of 1 MW capacity |
| Municipal Solid Waste | 41 TPD | 112 TPD |
| E- Waste | | 90 Kg/day |
| Biomedical Waste (500 beds) | | 825 Kg/day |

6. Water requirement of the project are as follows:

| Particulars | Unit/ Area | Population | Rate of Fresh Water supply norms | Fresh water KLD | Rate of Flushing Water supply | Flushing/ Recycled Water KLD | Total Water KLD |
|-------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Residential | 42500 | 212500 | 65 LPCD | 13813 | 21 LPCD | 4463 | 18275 |
| Floating (10% of Resd.) | | 21250 | 5 LPCD | 106 | 10 LPCD | 213 | 319 |
| Commercial | 774931 | 77493 | 5 LPCD | 387 | 10 LPCD | 775 | 1162 |
| School | 142209 | 2000 | 15 LPCD | 30 | 10 LPCD | 20 | 50 |
| Medical Facilities | 114501 | 500 beds | 340 Lit/Bed | 170 | | | 170 |
| Community Center | 11250 | 750 | 5 LPCD | 4 | 10 LPCD | 8 | 11 |
| Misc. | | | | 20 | | | 20 |
| Landscape Area | 152484.3 | | | | | 152 | 152 |
| HVAC | | | | | | 200 | 200 |
| DG Cooling | | | | | | 40 | 40 |
| Total Water Requirement | | | | 14530 | | 5870 | 20400 |

- Approx. 16 MLD waste water will be generated from the township which will be discharged into municipal sewer from where it will go into CSTP of GDA.
- Combined Sewage Treatment Plant (CSTP) of Ghaziabad Development Authority (GDA) is situated near the site. (Location is marked on the Layout Plan).
- Treated wastewater received from CSTP of GDA will be further treated at site for flushing, landscaping, Cooling and other low end uses.
- 7. The total water requirement is proposed as 20400 KLD which will be sourced from bore well/ Municipal Supply. Total fresh water requirement is proposed 14.6MLD.
- 8. The total waste water generation is proposed as 16 MLD treated in CSTP of GDA.
- 9. Total power requirement is proposed as 85 MW from UPPCL.
- 10. 7 nos. of DG Set of (71x MW) are proposed for power back up.
- 11. Total green area of the proposed project is 501000 m².
- 12. Solid Waste Management details are as follows:

| Particulars | Population | Waste (TPD) |
|---|------------|----------------|
| Residential | 212500 | 106.3 |
| Floating (10% of Residential) | 21250 | 3.2 |
| Commercial | 77493 sqm | 2.1 |
| School | 2000 | 0.5 |
| Medical Facilities | 500 beds | |
| Community Center | 11250 sqm | 0.3 |
| Total Municipal Waste | | 112 TPD |
| Horticulture waste (@0.0037 kg/sqm/day) | | 1.85 TPD |
| E waste (@0.15 kg/c/year) | | 112 Kg/day |
| Biomedical Waste (500 beds) | | 825 Kg/day |

- 13. The proposed number of rain water harvesting pits 380 will be provided.
- 14. The total excavated earth is 69354 m³.
- 15. Total No. of Block is 18.
- 16. The Project proposal falls under category 8"b" of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (meeting held on 04/10/2013), the State Level Environment Impact Assessment Authority (meeting held on 10/10/2013) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to the effective implementation of the following general and specific conditions:

A. General Conditions:

1. The proposed project shall be in conformity to land use approved by competent Authority.
2. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
3. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U P pollution control board before start of construction.
4. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
5. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent Authority shall be obtained in this regards.
6. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent Authority.
7. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
8. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
9. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.

10. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
11. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
12. Obtain necessary clearances from the competent Authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
13. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
14. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
15. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
- ✓ 16. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
- ✓ 18. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
19. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
20. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
21. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
22. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
23. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
24. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
25. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
26. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
27. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
28. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
29. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
30. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
31. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
32. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
33. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.

34. Prepare and present disaster management plan.
35. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
36. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
37. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
38. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
39. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
40. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
41. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
42. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
43. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority.
44. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
45. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
46. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
47. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
48. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
49. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
50. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
51. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
52. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
53. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
54. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
55. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
56. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
57. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
58. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.

59. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
60. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
61. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
62. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
63. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
64. Dispensary for first aid shall be provided.
65. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
66. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
67. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
68. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
69. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
70. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
71. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
72. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
73. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
74. Plan for safe disposal of R.O reject is to be submitted.
75. Project falling within 10 K.M. area of Wild Life Sanctuary should obtain a clearance from National Board for Wild Life (NBWL) even if the eco- sensitive zone is not earmarked.

B. Specific Conditions:

1. The project proponent will ensure that no fresh ground breaking is undertaken in 500 m from any environmental sensitive features.
2. The project proponent will not undergo any construction activities before all litigation related to project in respect of Municipal Solid Waste dump site of Dhundera are finally resolved.
3. The court decision related to litigation to project shall be final and implemented.
4. The project proponent will submit Corporate Social Responsibility (CSR) Plan amounting 2% of project Cost within 3 months or any way before commencement of construction.
5. Ground water recharging will be strictly followed.
6. Digging of basement shall be undertaken in view of structural safety of adjacent buildings under information/consultation with District Administration/Mining Department.
7. Sprinkler to be used for curing and quenching during construction phase. No ground water to be used for construction.
8. During the construction phase, a wheel wash arrangement shall be provided at all exit points of the site.
9. Environmental Corporate Responsibility (ECR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be submitted (within three month) on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in up-liftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The program can include activities such as old age homes, rain water harvesting provisions in nearby areas, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self employment and jobs. Separate budget for community development activities and income generating programmes shall be specified.
10. Use of LEDs should be ensured in place of CFL. Solar light is to be provided in the common areas with 50% of them may be with dual power.

11. Motion sensor based lights to be provided in parking areas, corridors, passages, aisles, stairways.
12. Photoelectric lighting should be provided on all the open areas/roads.
13. All internal and peripheral roads should be minimum 9 m. wide and all entry & exit should be bell mouth shaped.
14. The three tier Green Belt shall be raised all around the plant site which shall comprise of not less than 33% of the total area. The project proponent shall ensure that the density of trees are not less than 2500 per ha and rate of survival of plantation shall be not less than 80%. The selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the DFO.
15. STP to be constructed during construction phase. 100% waste water is to be treated in STP conforming to prescribe standards of receiving body or designated use. Monitoring of STP to be done weekly till its stabilizations then monthly. The excess treated waste water after in-house use may be given to nearby builders for construction or discharge into public drainage system/drains after permission from the competent authority
16. As committed during presentation zero discharge (no effluent outside the project) be achieved
17. 100 % provision of Rain Water Harvesting is to be made. RWH shall be initially done only from the roof top. RWH from green and other open areas shall be done only after permission from CGWB. RWH pits shall be relocated towards wider open area available for ground water recharge.
18. Dedicated guest parking at surface should be provided.
19. Manure generated from STP/organic waste converter shall be used in-house and plan for management of surplus be submitted within three (3) months.
20. Stack Height should be calculated based on combined D.G. sets capacity and shall be higher than the tallest building in the project.
21. The total excavated soil will be completely utilized at project site for leveling and back filling. The top soil generated during basement construction will be used for plantation and green area development. The management of surplus soil, if any, will be transported and managed in Eco-friendly manner and the plan will be submitted within 3 month.
22. Crèche to be provided during the construction and operation phase.
23. Provision of separate dedicated room to be made for senior citizen commensurate with proper amenities (TV, music system, indoor games etc.) for end user in and around the club house.
24. E-waste shall be managed as per e-waste Management and Handling Rules 2011. Temporary storage at secure place is made till it is given to recycler approved by CPCB.
25. A temporary separate and isolated MSW storage and transfer room should be provided at least for two days in a manner to avoid generation of foul smell.
26. Ground water should not be extracted for the purpose of construction or otherwise. In case of default the Environmental Clearance will deem to be cancelled.
27. Post project monitoring for air, water (surface+ground), Stack (including CO and HC) noise and STP to be carried out as CPCB/SPCB guidelines.
28. Adequate Ventilation arrangement in the basement should be provided along with installation of CO Monitors.
29. The basement should be constructed in consultation with CGWB to avoid any infringement of ground water table.
30. Project falling within 10 Km. area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
31. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any Wetlands/Ponds within the project area as per revenue records if any should be protected and brought to the notice of forest department / SEIAA for directions.

32. Project proponent should procure all the regulatory clearances and completion certificate from the development authority before handing over the possession of dwellings to residents.
33. The project proponent to ensure that buffer zone of no activity/development as declared /identified under any law does not fall around the project boundary.

It shall be ensured that proposed power backup for the project should be less than 05 MW. Also, no construction is to be started without obtaining Prior Environmental Clearance. Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This environmental clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for Ghaziabad by the competent Authority. In case of violation, it would not be effective and would automatically stand cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearances should be obtained.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(J.S. Yadav)

Member Secretary, SEIAA

Dated: As above

No...../Parya/SEAC/1608/2013/TA(J)

Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Ghaziabad, U.P.
6. Deputy Director, Regional Office, Directorate of Environment, Meerut.
7. Copy for Web Master/Guard file.


(O.P. Varma)

Director (I/c)/Secretary, SEAC
Directorate of Environment